

पत्रांक— 5335

न०वि०एवंआ०वि०

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,  
नगर निगम गया।

पटना, दिनांक 19/8/16

विषय :- माह जुलाई 2016 की मासिक समीक्षा टिप्पणी के संबंध में।

महाशय,

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आपके कार्यों की मासिक समीक्षा की जा रही है। माह जुलाई तक प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा से निम्न तथ्य विदित होते हैं :-

**1. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग :-**

(i) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत दिनांक 01.04.2016 को आपके नगर निकाय में 34.51 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2016-17 में 00.00 लाख रुपये विमुक्त हुए। कुल उपलब्ध 34.51 लाख रुपये संसाधनों में से अद्यतन व्यय 4.67 लाख रुपये है, जो मात्र 13.53 प्रतिशत है। स्पष्टतः आपकी उपलब्धि अत्यंत निराशाजनक है।

**2. 13वें वित्त आयोग :-**

(i) 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत दिनांक 01.04.2016 को आपके नगर निकाय में 0.00 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2016-17 में 0.00 लाख रुपये विमुक्त हुए। कुल उपलब्ध 0.00 लाख रुपये संसाधनों में से अद्यतन व्यय 0.00 लाख रुपये है, जो मात्र 0.00 प्रतिशत है।

**3. 14 वें वित्त आयोग:-** 14 एवं वित्त आयोग के अंतर्गत दिनांक 01.04.2016 को आपके नगर निकाय में 1028.01 लाख रुपये उपलब्ध थे | वर्ष 2016-17 में 706.46 लाख रुपये विमुक्त हुए | कुल उपलब्ध 1734.47 लाख रुपये संसाधनों में से अद्यतन व्यय 914.79 लाख रुपये है, जो की मात्र 52.74 प्रतिशत है | स्पष्टतः आपकी उपलब्धि संतोषजनक है।

**4 राज्य योजना :**

(i) राज्य योजना अंतर्गत दिनांक 01.04.2016 को आपके नगर निकाय में 1830.66 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2016-17 में 0.00 लाख रुपये विमुक्त हुए। | कुल

उपलब्ध 1830.66 लाख रुपये संसाधनों में से अद्यतन व्यय 55.04 लाख रुपये है।  
जो मात्र 3.01 प्रतिशत है।

- (ii) भौतिक प्रतिवेदन की समीक्षा करने से ज्ञात है कि दिनांक 01.04.2016 को 22 योजनाएं लंबित थीं। वर्ष 2016-17 में अब तक 43 योजनाएं ली गयी हैं। इस प्रकार कुल कार्यरत 65 योजनाओं में से अभी तक 21 योजनाएं पूर्ण हुई हैं। स्पष्टतः आपकी उपलब्धि *निराशाजनक* है।

#### 5. पंचम वित्त आयोग:-

पंचम वित्त आयोग के अंतर्गत दिनांक 01.04.2016 को आपके नगर निकाय में 1798.21 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2016-17 में 0.00 लाख रुपये विमुक्त हुए। कुल उपलब्ध 1798.21 लाख रुपये संसाधनों में से अद्यतन व्यय 995.80 लाख रुपये है, जो की मात्र 55.38 प्रतिशत है। स्पष्टतः आपकी उपलब्धि असंतोषजनक है।

#### 6. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF):-

- (i) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत दिनांक 01.04.2016 को आपके नगर निकाय में 83.47 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2016-17 में 0.00 लाख रुपये विमुक्त हुए। कुल उपलब्ध 83.47 लाख रुपये संसाधनों में से अद्यतन व्यय 30.37 लाख रुपये है, जो मात्र 36.38 प्रतिशत है।
- (ii) भौतिक प्रतिवेदन की समीक्षा करने से ज्ञात है कि दिनांक 01.04.2015 को 73 योजनाएं लंबित थीं। वर्ष 2015-16 में अब तक 71 योजना ली गयी हैं। इस प्रकार कुल कार्यरत 144 योजनाओं में से अभी तक सिर्फ 141 योजनाएं पूर्ण हुई हैं। स्पष्टतः आपकी उपलब्धि संतोषजनक है।

#### 7. ठोस अवशिष्ट प्रबंधन :-

- (i) आपके शहर में कुल 53 वार्ड हैं, जिसमें से अभी तक 25 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण का कार्य हो रहा है।
- (ii) सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यांत्रिकरण पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन वांछित संख्या में मशीनों का क्रय नहीं किया गया है। शहर में कार्यरत सफाई कर्मियों की ससमय उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है, इसका अनुपालन अप्राप्त है। ठोस अवशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन एवं निष्पादन के लिए की जा रही कार्रवाई का प्रतिवेदन अपेक्षित है।

8. मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान :- मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान योजना के अंतर्गत दिनांक 01.04.2015 को आपके नगर निकाय में 0.00 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2015-16 में 437.87 लाख रुपये विमुक्त हुए। कुल उपलब्ध 437.87 लाख रुपये

संसाधनों में से दूरभाष पर प्राप्त सूचना के अनुसार अद्यतन व्यय 435.15 लाख रुपये है।

**9. उपयोगिता प्रमाण पत्र :-**

आपके निकाय के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2014-15 तक की अवधि में कुल 16461.543 लाख की राशि विभाग द्वारा आवंटित की गयी थी जिसके आलोक में अभी तक कुल 10593.62 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा की गयी है। आपके पत्रांक 1760 दिनांक 01.12.2014 द्वारा 2457.10 लाख की राशि अप्राप्त है और 3410.82 लाख की राशि अभी तक समायोजित के लिए लंबित है। लंबित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अगले 7 दिनों के अंदर विभाग में जमा करें।

**10. नगर सेवा प्रबंधन :-** आपके शहर से संबंधित इस वित्तीय वर्ष में हेल्पलाईन के माध्यम से 61 जन शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 12 का निराकरण किया गया है, एवं 49 लंबित हैं। स्पष्टतः आपकी उपलब्धि *अत्यंत निराशाजनक* है।

**11. होल्डिंग टैक्स :-** माह जुलाई 2016 का मासिक संग्रहण 57.15 लाख रुपये है, जो की वित्तीय वर्ष की औसत मासिक संग्रहण 56.60 लाख रुपये से 33.45 प्रतिशत अत्यधिक है। चालू वित्तीय वर्ष का वार्षिक औसत मासिक संग्रह 75.53 है। दिनांक 01.04.2016 को होल्डिंग की संख्या 61920 थी एवं अद्यतन तिथि तक 64458 होल्डिंग ही है। होल्डिंग का सर्वेक्षण करके अतिरिक्त होल्डिंग को होल्डिंग टैक्स के दायरे में लाने के लिए किये गये प्रयास जारी रहे।

**12. अन्य स्रोतों से कर :-**

अन्य स्रोतों से कर वसूली 170.05 लाख रुपये है, जिसमें सुधार लाने का प्रयास करें

**13. स्वच्छ भारत मिशन :-** स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिए गए कुल लक्ष्य 1334 एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिए गए कुल लक्ष्य 2668 अर्थात् कुल लक्ष्य 4002 के विरुद्ध आपके निकाय में 160 व्यक्तिगत एवं 3 सामूहिक शौचालय का निर्माण हुआ है लेकिन Public Toilet नहीं बने हैं। इस पर जोर दिया जाय।

**14. सबके लिए आवास :-** सबके लिए आवास (HFA) योजनान्तर्गत आपके नगर निकाय में वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा 1249 घर बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें से 579 लाभार्थियों के विवरण को भारत सरकार के MIS Online Portal पर इंट्री की गई है। आपके द्वारा अब तक 100 Beneficiaries record (अभिलेख)

खोली गई है लेकिन अब तक एक भी लाभार्थी को प्रथम क्रिस्त की राशि का RTGS नहीं किया गया है। कृपया इसमें और तेजी लाने का प्रयास करें।

**15. पी०एल०खाता:-**

दिनांक 01.04.2016 को आपके नगर निकाय के पी० एल० खाते में 3924.89 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2016-17 में 392.06 लाख राशि विमुक्त की गई है। इस प्रकार कुल उपलब्ध 4316.95 लाख की राशि में से 1389.53 लाख मात्र राशि का भुगतान किया गया है। शेष 2927.42 लाख की अव्यवहृत अंतिम राशि (Closing Balance) अभी भी मौजूद है जो अत्यंत ही बड़ी राशि है।

**16.लंबित अंकेक्षण :-**

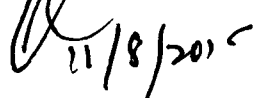
आपके नगर निकाय के विरुद्ध निम्नलिखित अंकेक्षण प्रतिवेदन लंबित है :-

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०	वर्ष	अनुपालन प्रतिवेदन की स्थिति
1204/2014-15	2013-14	अप्राप्त

उपर्युक्त लंबित कंडिकाओ का निष्पादन अगले 7 दिनों के अंदर विभाग में जमा करें जिससे इसपर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

निर्देश दिया जाता है कि इस मासिक समीक्षा टिप्पणी में अंकित तथ्यों पर लिखित अनुपालन प्रतिवेदन पत्र निर्गत होने के तीन सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से विभाग को प्रेषित किया जाय। इस मासिक समीक्षा टिप्पणी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जा रहा है। साथ ही आपके द्वारा समर्पित किये जा रहे मासिक समीक्षा टिप्पणी का अनुपालन प्रतिवेदन भी वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।

विश्वासभाजन



(चैतन्य प्रसाद ),

प्रधान सचिव